हिन्दी दैनिक

स्वाभिमान जागरण

RNI.No.- UPHIN/2021/84176

लखनऊ से प्रकाशित..

वर्ष : 04 अंक : 333 लखनऊ, गुरूवार 29 अक्टूबर 2026 पृष्ठ : 08 मूल्य : 1.00 रूपया

संक्षिप्त खबरें

कुंभ मेले की यादें होंगी खास, नासिक–त्र्यंबकेश्वर के लिए जारी होंगे विशेष डाक टिकट

एजेंसी

नासिक। सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 के अवसर पर नासिक और त्र्यंबकेश्वर की आध्यात्मिक विरासत को दर्शाने वाले विशेष डाक टिकट जारी किए जाएंगे। डाक विभाग की माय स्टैम्प पहल के तहत इस क्षेत्र के दो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों नासिक के रामकुंड और त्र्यंबकेश्वर के कुशावर्त तीर्थ को इन डाक टिकटों पर चित्रित किया जाएगा। इन डाक टिकटों का अनावरण 31 अक्टूबर को कुंभ के ध्वजारोहण के दिन किया जाएगा। इस समारोह के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य भारत की आध्यात्मिक विरासत को सहेजने और प्रदर्शित करने के लिए डाक टिकटों को एक माध्यम बनाकर नासिक–त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र की ध ार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर को देश भर के लोगों तक पहुंचाना है। रामकुंड इस क्षेत्र के सबसे पवित्र स्नान स्थलों में से एक है और वैष्णव संप्रदाय के लिए इसका विशेष महत्व है।

महंगाई पर खरगे का मोदी सरकार पर वार, बोले, अच्छे दिन के इंतजार में बीत गए 12 साल

एजेंसी

नयी दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि वोट का अधिकार छीनने पर उतारू मोदी सरकार अब जीवन जीने का अधिकार भी खत्म करना चाहती है। खरगे ने सोशल मीडिया एक्स पर बुधवार को लिखा कि त्योहारों के बीच कमरतोड़ महंगाई जनता की कमाई का एक–एक पैसा निगल रही है। उनका कहना था कि आवश्यक वस्तुओं की कीमत आसमान छू रही है जिससे लोगों का जीवन कठिन बना दिया है। उन्होंने महंगाई से जुड़े आंकड़े देते हुए कहा कि खाद्य महंगाई दर 2.13 प्रतिशत से बढ़कर 7.74 प्रतिशत पहुंच गई है, घरेलू कर्ज 36.7 प्रतिशत बढ़ा है, घरेलू वित्तीय बचत में चार प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि खुदरा महंगाई 5. 54 प्रतिशत और थोक महंगाई 11.39 प्रतिशत है।

2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य

एजेंसी

नयी दिल्ली। भारत ने 2030 तक प्रतिवर्ष 50 लाख मीट्रिक टन (5 एमएमटी) ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। बुधवार को जारी एक आधिकारिक फैक्टशीट के अनुसार, यह पहल देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने और भारत को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का मानना है कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत को अधि ाक स्वच्छ, आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी ऊर्जा अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। मिशन के तहत वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन आयात पर होने वाले कुल खर्च में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बचत का अनुमान है। इस मिशन का उद्देश्य केवल ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना नहीं, बल्कि औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन को भी नई गति देना है।

'साहस के साथ नई खोज करें, दुनिया का नेतृत्व करें': प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भविष्य की तकनीकों पर भारत को ऐतिहासिक आह्वान

एजेंसी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, जो देश के युवा इनोवेटर्स के आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा और विचारों से प्रेरित है। कार्यक्रम से पहले स्टार्टअप प्रतिनिधियों के साथ हुई अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए, पीएम मोदी ने कहा, दशकों पहले एक समय ऐसा था जब भारत के लिए विज्ञान और तकनीक का मतलब सिर्फ दूसरों की बराबरी करना (बंजबी नच) होता



उनकी बड़ी महत्वाकांक्षाओं और नए विचारों पर काम करने के उनके आत्मविश्वास की सराहना की। उन्होंने कहा, ष्भारत के युवा जिस स्तर पर सोच रहे हैं और जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वह वाकई प्रेरणादायक है। कॉन्क्लेव की थीम इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी (उभरते विज्ञान और तकनीक) का जिक्र करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक प्रगति को लेकर भारत के दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव आया है। पहले, भारत अक्सर विदेशों में विकसित तकनीकों को अपनाता था– कभी–कभी तो उनके आने के कई सालों बाद– और उनमें बस थोड़े–बहुत सुधार कर लेता था। उन्होंने कहा, दशकों पहले एक समय ऐसा था जब भारत के लिए विज्ञान और तकनीक का मतलब सिर्फ दूसरों की बराबरी करना (बंजबी नच) होता था। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, ष्जब दुनिया में कोई नई खोज होती थी, तो वह तकनीक हम तक कई सालों बाद पहुँचती थी। हम उसे अपना लेते थे या उसमें मामूली सुधार करके आगे बढ़ाते थे। उन्होंने कहा कि अब भारत एक अलग रास्ते पर चल रहा है। इसमें अब कहीं अधिक आत्मविश्वास है और एक बड़ी महत्वाकांक्षा है– ऐसी तकनीकें विकसित करना जो देश की जरूरतों के साथ–साथ वैश्विक आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ष्लेकिन आज, 21वीं सदी का भारत एक नई सोच और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा, अब हमारा लक्ष्य– भारत के लिए, दुनिया के लिए, आज के लिए और आने वाले कल के लिए–नई तकनीकें विकसित करना, उनकी दिशा तय करना और वैश्विक चुनौतियों से निपटने की क्षमता तैयार करना है। दूसरों के पीछे चलने के बजाय नेतृत्व करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, ष्भारत को भविष्य की तकनीकों को अपनाना चाहिए, साहस के साथ नवाचार (इनोवेशन) करना चाहिए और इन तकनीकों को बनाने में दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए। अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के मंगल मिशन और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास सफल लैंडिंग का उदाहरण दिया, जो भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दिखाते हैं। उन्होंने कहा, ष्हम अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंच गए। हम चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे, जहां पहले कोई नहीं पहुंच पाया था।ष इन उदाहरणों के जरिए यह बताया गया कि भारत न केवल दूसरे देशों द्वारा विकसित तकनीकों पर निर्भर रहने के बजाय, बल्कि जटिल वैज्ञानिक मिशनों को पूरा करने और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में भी सक्षम है।

एसआईआर रद्द करने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग, एमके स्टालिन ने राष्ट्रपति को भेजी याचिका

एजेंसी

नयी दिल्ली। तमिलनाडु की राजनीति में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विवाद तेज हो गया है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को याचिका भेजकर



एसआईआर प्रक्रिया रद्द करने और चुनाव में बैलेट पेपर की व्यवस्था दोबारा लागू करने की मांग की है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठाई है। स्टालिन ने मतदाता सूची से कथित तौर पर 97 लाख नाम हटाए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से बाहर होने के कारणों की जांच होनी चाहिए। साथ ही यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि नाम हटाए जाने का चुनाव परिणामों पर कोई असर पड़ा या नहीं। स्टालिन की याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त के कथित पक्षपातपूर्ण आचरण को लेकर संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है। उनके मुताबिक, चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखना बेहद जरूरी है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 86(2) के तहत संसदीय संदर्भ शुरू करने की मांग का भी उल्लेख किया गया है। स्टालिन ने तमिलनाडु में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामले की समीक्षा के लिए अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय लेने की अपील भी की है। इन मांगों पर संबंधित संवैधानिक संस्थाओं की ओर से क्या कदम उठाया जाता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। डीएमके प्रमुख ने मांग की है कि एसआईआर प्रक्रिया से पहले की मतदाता सूची बहाल की जाए। उनका तर्क है कि मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और किसी भी पात्र नागरिक को मतदान के अधि ाकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। स्टालिन ने कहा कि मतदान केवल विशेषाधिकार नहीं, बल्कि संविध ाान से जुड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है। इसलिए हर पात्र मतदाता का नाम सूची में होना और उसके वोट की गणना सुनिश्चित करना जरूरी है। स्टालिन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी दोहराई है। उनका कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। एसआईआर और चुनाव प्रणाली को लेकर विपक्षी दलों की आपत्तियों के बीच यह मांग राजनीतिक बहस को और तेज कर सकती है। हालांकि, मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के आंकड़ों, उनके कारणों और चुनाव परिणामों पर संभावित प्रभाव का आकलन आधि ाकारिक दस्तावेजों तथा जांच के आधार पर ही किया जा सकता है।

महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामला

कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया

एजेंसी

नयी दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को बृजभूषण शरण सिंह को, उनके बरी होने के खिलाफ दायर अपील पर जवाब दाखिल करने का



एक आखिरी मौका दिया। आरोपी के वकील ऑनलाइन पेश हुए और जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा। महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। 3 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट ने डब्लयूएफआई के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण और तत्कालीन सचिव विनोद तोमर को यौन उत्पीड़न के मामले से बरी कर दिया था। विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया और मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर के लिए तय की। राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) मनीष रावत पेश हुए। 28 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को नोटिस जारी किया था।कोर्ट ने निर्देश दिया था कि पीड़ितों के नाम वाले मूल हलफनामे और आदेशों को एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाए। कोर्ट ने अपीलकर्ता को यह भी निर्देश दिया था कि वे याचिका की एक ऐसी प्रति दाखिल करें जिसमें पीड़ितों के नाम हटा दिए गए हों। पहलवानों ने बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए तर्क दिया है कि यह कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं है और साक्ष्यों के पूरी तरह से गलत और चुनिंदा मूल्यांकन पर आधारित है। अपील में कहा गया है कि यह आदेश केवल अटकलों और अनुमानों पर आधारित है। इसमें कानून के स्थापित सिद्धांतों को लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा, इसका तर्क यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के अपेक्षित व्यवहार के बारे में पुरानी और रूढ़िवादी धारणाओं पर टिका है, न कि पीड़ितों की परिस्थितियों को ध यान में रखते हुए साक्ष्यों के निष्पक्ष मूल्यांकन पर। यह मामला उस एफआईआर से जुड़ा है जिसे महिला पहलवानों ने तब दर्ज कराया था, जब बृजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्लयूएफआई) के प्रमुख थे। दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 354 डी, 354 ए, 506 (1) और 109 लगाई थी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) अश्वनी पंवार ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया। सुनवाई बंद कमरे (बंद कोर्टरूम) में हुई। बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर पर उस मामले में मुकदमा चला, जो भारत और विदेशों में महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा था। ये आरोप तब लगे थे जब बृजभूषण शरण सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (डब्लयूएफआई) के प्रमुख थे। महिला पहलवानों ने जंतर–मंतर पर विरोध ा प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। एक महिला पहलवान की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की थी।

राज्यसभा उपचुनाव, मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी होंगे भाजपा उम्मीदवार

एजेंसी

नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केंद्रीय चुनाव समिति ने मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नाम पर मुहर लगा दी है। पार्टी ने बुधवार को उनके नाम की आधिकारिक घोषणा की। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम घोषित कर दिया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, यदि मतदान की आवश्यकता हुई तो 12 नवंबर 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसके बाद मतगणना होगी। उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 26 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 2 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 3 नवंबर को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 5 नवंबर निध ार्गारित की गई है। इस उपचुनाव में मध्य प्रदेश विधानसभा के विधायक राज्यसभा सदस्य का चुनाव करेंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन पत्र विधानसभा भवन, भोपाल स्थित रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। दरअसल,



डॉ. एल. मुरुगन अप्रैल 2024 में मध य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उन्होंने 14 अक्टूबर 2026 को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 3 अप्रैल 2030 तक था। उनके इस्तीफे के बाद रिक्त हुई सीट पर अब उपचुनाव कराया जा रहा है। उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश विधानसभा के अपर सचिव उमेश शर्मा को रिटर्निंग ऑफिसर और अपर सचिव मयंक वर्मा को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है। विधानसभा भवन स्थित समिति कक्ष संख्या दो (एम–2) को निर्वाचन कार्यालय के लिए अधि ाकृत किया गया है। भाजपा ने भी इस उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई थी। अब केंद्रीय चुनाव समिति ने हरदीप सिंह पुरी के नाम को मंजूरी देकर उम्मीदवार के नाम पर स्थिति स्पष्ट कर दी है।

वकील बनाम पुलिस विवाद गहराया, सेंट्रल दिल्ली बार एसोसिएशन ने दी दिल्ली पुलिस मुख्यालय का घेराव करने की चेतावनी

एजेंसी

नयी दिल्ली। दिल्ली पुलिस के एसीपी द्वारा सेंट्रल दिल्ली बार एसोसिएशन के सचिव और वकील को धमकी देने और रिवॉल्वर दिखाने के विरोध ा में वकीलों का विरोध–प्रदर्शन बुध ावार को जारी रहा। इस दौरान सेंट्रल दिल्ली बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एडवोकेट विकास त्रिपाठी ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो गुरुवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय का घेराव करेंगे। उन्होंने संबंधित एसीपी को सस्पेंड करने की भी मांग की है। सेंट्रल दिल्ली बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और वकील विकास त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ष्दिल्ली पुलिस रक्षक के बजाय भक्षक बन गई है। जब भी लोगों को कोई समस्या होती है या कोई अपराध होता है, तो वे सबसे पहले दिल्ली पुलिस के पास जाते हैं। अगर पुलिस उनकी बात नहीं सुनती, तो वे वकीलों और अदालतों के पास आते हैं। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस के सामने वकीलों को भी बेबस करने की कोशिश की जाएगी, तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। विकास त्रिपाठी ने कहा, ष्हमारे बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी दिल्ली पुलिस के पास गए थे और उनके खिलाफ एसीपी ही बंदूक में गोलियां भर रहा था। इसका वीडियो भी मौजूद है। एसीपी की ऐसा



करने की हिम्मत कैसे हुई? उन्हें इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा और जब तक उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाता, तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। गुरुवार को हम लोग दिल्ली पुलिस मुख्यालय का घेराव करेंगे। इससे पहले मंगलवार को सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव विजय बिश्नोई ने आईएएनएस से बातचीत में कहा था, ष्दिल्ली पुलिस के एक एसीपी ने शिकायतकर्ता बनकर हमारे साथी वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसकी शुरुआत 23 तारीख को हुई, जब शाहदरा इलाके में कुछ वकीलों के बीच बहस हो गई थी। हमारे एक वकील के सिर में चोट आई और उन्हें 7–8 टांके लगे। इसके बावजूद, काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने धारा 308 के तहत मामला दर्ज किया। केस दर्ज होने के बाद आरोपी पुलिस स्टेशन में मौजूद थे और यह भरोसा दिया गया था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

आंध्र प्रदेश में कहर, तीन लोगों की मौत, सैकड़ों पेड़ उखड़े, सड़कें क्षतिग्रस्त

एजेंसी

अमरावती। चक्रवात अर्नब से आंध्र प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित हुआ है और राज्य में तीन लोगों की मौत हो गई तथा 31 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के एक वरिष्ठ अधि ाकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक (आईजी) नरेन्द्र सिंह बुंदेला ने यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि केंद्र सरकार के साथ–साथ आंध्र प्रदेश और ओडिशा की आपदा राहत एवं बचाव टीमें बारिश से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही हैं। दोनों राज्यों और आसपास के इलाकों में बारिश जारी रहने की संभावना है। उन्होंने बताया कि चक्रवात पुडुचेरी के यनम के पास तट को पार कर गया है और कमजोर होकर अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान से भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। इसके धीरे–धीरे और कमजोर होकर पहले चक्रवाती तूफान और फिर शाम तक गहरे दबाव के क्षेत्र में बदलने का अनुमान है। बुंदेला ने कहा, चक्रवात अर्नब से आंध्र प्रदेश का उत्तरी हिस्सा और ओडिशा का दक्षिणी हिस्सा सबसे अधिक प्रभावित हुआ है।



दोनों राज्यों के कुछ जिलों में तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है। उन्होंने कहा, आंध्र प्रदेश सबसे अधि ाक प्रभावित हुआ है। हमें जानकारी मिली है कि वहां पेड़ उखड़ गए हैं, विभिन्न प्रकार के 31 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और तीन लोगों की मौत हो गई है।ष्श बुंदेला ने कहा, श्श्प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा में चक्रवात का कोई गंभीर असर नहीं पड़ा है। महानिरीक्षक ने बताया कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अलावा पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना तथा पुडुचेरी और अंडमान–निकोबार द्वीपसमूह में एनडीआरएफ की कुल 39 टीम तैनात की गई हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार रात एनडीआरएफ की चार अतिरिक्त टीम आंध्र प्रदेश भेजी गईं। बुंदेला ने कहा कि आंध्र प्रदेश में करीब 57,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया, जबकि मंगलवार रात यनम से 38 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान श्अर्नबश मंगलवार देर रात दो बजे से बुधवार सुबह आठ बजे के बीच आंध्र प्रदेश और यनम के तटों को पार कर गया और कमजोर होकर भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया। मौसम विभाग ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, चक्रवात ने 16.450 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 81.90 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास यनम के दक्षिण–पश्चिम में आंध्र प्रदेश और यनम के तटों को पार किया। यह स्थान नरसापुर से लगभग 20 किलोमीटर पूर्व–उत्तर पूर्व, यनम से 40 किलोमीटर दक्षिण–पश्चिम और काकीनाडा से 60 किलोमीटर दक्षिण–पश्चिम में है।

सम्पादकीय

स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए एक और चुनौती

मोदी सरकार के 12 वर्षों में भारत में प्रेस की आजादी काफी ज्यादा खतरे में पड़ चुकी है। कार्पोरेट पूंजी ने स्वतंत्र पत्रकारिता पर कई तरह की बेड़ियां लगा ही दी हैं, ऊपर से सरकार के रवैये ने भी निर्भीक, स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता को काफी नुकसान पहुंचाया है। सरकार ने निजता की सुरक्षा के नाम पर जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण का कानून बनाया है, वह भी अब पत्रकारिता की राह में बड़ा रोड़ा बन रहा है। इस बाधा को दूर करने के लिए डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। डीएनपीए की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि डीएनपीए के माध्यम से 21 समाचार प्रकाशकों ने कानून के प्रावधानों को चुनौती दी है। जिनमें वे मीडिया संस्थान भी शामिल हैं, जिनके मालिकाना हक गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के पास हैं। मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची तथा जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने डीएनपीए की याचिका पर सुनवाई की और केंद्र सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख दी है। हालांकि केंद्र सरकार को नोटिस जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कानून की वैधता और उसके प्रावधानों पर अंतिम निर्णय होना बाकी है और यहीं सारा पेंच फंसा हुआ है। क्योंकि अगर अदालत का फैसला कानून निरस्त करने या इसमें प्रावधानों में संशोधनों वाला हुआ, तब तो खोजी पत्रकारिता के लिए उम्मीद बची रहेगी। वर्ना फिर बड़े घोटालों की पोल खोलने वाली खबरें बनाने का जोखिम भरा काम शायद ही हो पाए। ध्यान रहे कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 भारत का पहला व्यापक डेटा संरक्षण कानून है, जिसे 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। इस कानून का मकसद नागरिकों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा डेटा के वैध उपयोग के बीच संतुलन बनाना। केंद्र सरकार ने इससे संबंधित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025, पिछले साल 14 नवंबर को अधिसूचित किए हैं। नियमों का उल्लंघन करने या डेटा सुरक्षा में चूक होने पर श्डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड्य द्वारा 250 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। तकनीकी विकास के इस वक्त में डेटा लीक होने और व्यक्तिगत जानकारियां गलत हाथों में पड़ने के खतरे वाकई बहुत बढ़ चुके हैं। इस लिहाज से निजता की सुरक्षा के प्रावधान करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसकी आड़ में गलत बातों पर पर्दा डालने और उन खबरों को बाहर आने से रोकने की चालाकी हो, तो फिर सवाल उठने जायज हैं। मीडिया संगठनों का कहना है कि इस कानून के प्रावधान खोजी पत्रकारिता को बाधित कर सकते हैं, सूचना पाने के मौलिक अधिकार को प्रभावित कर सकते हैं और पत्रकारों के गोपनीय सूत्रों की पहचान उजागर होने का खतरा पैदा कर सकते हैं। मीडिया संगठनों की चिंता है कि व्यक्तिगत डिजिटल डेटा की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियम यदि पत्रकारिता पर भी उसी तरह लागू होते हैं, तो भ्रष्टाचार, कॉरपोरेट अनियमितताओं, चुनावी गड़बड़ियों और सरकारी कामकाज की जांच करना मुश्किल हो सकता है। डीएनपीए की दलील है कि कानून के नोटिस और सहमति से जुड़े प्रावधानों को पत्रकारिता पर लागू करने से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में उसकी निजी जानकारी जुटाने या उसकी गतिविधियों की जांच करने से पहले पत्रकारों को उसे सूचना देनी पड़े या उसकी सहमति लेनी पड़े। इसे आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं या कोई खोजी पत्रकार किसी के भ्रष्ट कामों का पता लगा भी ले, तो भी उसे उजागर करने से पहले उसे संबंधित व्यक्ति को ही सूचना देनी होगी। और जाहिर है कि उसके बाद वह उस खबर को शायद ही सामने ला पाए, क्योंकि फिर उस खोजी पत्रकार पर व्यक्तिगत डेटा मिटाने के अधिकार का इस्तेमाल खबर को दबाने या उनमें बदलाव कराने की मांग के लिए किया जा सकता है। मीडिया समूहों की आपत्ति का मूल सवाल यह है कि व्यक्तिगत निजता की रक्षा और स्वतंत्र पत्रकारिता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। उनका कहना है कि निजता की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन ऐसे नियमों से पत्रकारों की जनहित में जानकारी जुटाने और प्रकाशित करने की क्षमता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। रिपोर्टों के मुताबिक, मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच अगस्त में हुई बैठक में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा को लेकर आश्वासन दिया गया था। लेकिन डीएनपीए का कहना है कि पत्रकारों के लिए कानून में स्पष्ट लिखित छूट नहीं होने से उसकी चिंताएं दूर नहीं हुई हैं। एसोसिएशन ने इस मुद्दे को केवल तकनीकी या डेटा प्रबंधन से जुड़ा विवाद नहीं माना है। उसके मुताबिक, कानून के कुछ प्रावधानों का असर यह हो सकता है कि समाचार संस्थान जनहित से जुड़े मामलों की जांच और रिपोर्टिंग करते समय कानूनी कार्रवाई या आर्थिक दंड के जोखिम से बचने के लिए जरूरी खबरें प्रकाशित करने से पीछे हटें। बहरहाल, अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, जहां से भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता के बने और बचे रहने का रास्ता तय हो सकता है। क्योंकि सरकार के हित में तो यही है कि चाटुकार पत्रकार उसके कार्यकर्ता की तरह काम करते रहें। लेकिन यह देशहित में कतई नहीं है। अच्छी बात यह है कि जिन मीडिया संस्थानों पर सरकार के लिए काम करने के आरोप लगते रहे हैं, उनमें से भी कुछ इस कानून के प्रावधानों पर सवाल उठा रहे हैं।

त्यौहार के समय जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतें परिवारों के बजट पर भारी

कल्याणी शंकर

त्यौहारी मौसम के दौरान आने वाली ये आर्थिक चुनौतियां उन छोटे व्यवसायों को प्रभावित कर सकती हैं, जो पूरी तरह से अपनी बिक्री पर निर्भर हैं। बढ़ती कीमतें मुनाफे के मार्जिन को कम कर सकती हैं, लेकिन ये हाथ से बनी वस्तुओं के महत्व को भी उजागर करती हैं। अनोखे और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद पेश करके, स्थानीय विक्रेता उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं जो असली और पारंपरिक चीजों की तलाश में हैं। भारत में त्यौहार एक महत्वपूर्ण परम्परा है, सिर्फ जश्न मनाने का मौका नहीं। इसलिए इस दौरान परिवार नए कपड़े, मिठाइयां, सजावट के सामान और उपहार खरीदने पर काफी पैसा खर्च करते हैं। हालांकि, बढ़ती कीमतें और महंगाई उपभोक्ताओं को अपना बजट और खरीदारी के तरीके बदलने पर मजबूर कर रही हैं। कई परिवार अब त्यौहारों को छोटे स्तर पर मना रहे हैं और सस्ती चीजें तलाश रहे हैं। मौसम के अनिश्चित मिजाज के कारण प्याज, लहसुन और अदरक जैसी जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल आया है। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है। इससे परिवहन और खनिज तेल की लागत बढ़ गई है। थोक बाजार में खनिज तेल की कीमतें पिछले साल के मुकाबले करीब 40 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। कोर महंगाई दर बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गई है, जिसका असर खाने–पीने की चीजों, ईंधन, सेवाओं और अन्य सामानों की कीमतों पर पड़ रहा है। महंगाई को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए सिर्फ मौद्रिक नीति काफी नहीं है। इसके लिए समन्वित राजकोषीय उपायों की भी जरूरत है। इसमें नकदी प्रवाह का प्रबंधन, करों में बदलाव, और कृषि तथा आपूर्ति श्रृंखला में सुधार जैसे कदम शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति ने रेपोरेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी करके इसे 5.50 प्रतिशत कर दिया है। लगभग चार वर्षों में यह पहली बार है जब दरों में बढ़ोतरी की गई है। नीतिगत रुख को कड़ा से बदल कर नरपेक्ष करने का मतलब है कि निकट भविष्य में दरों में कटौती की संभावना कम है। मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष और कमजोर मानसून के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे महंगाई को लेकर चिंताएं और गहरी हो गई हैं। नतीजतन, अगले एक साल में दरों में 100 बेसिस पॉइंट्स से ज्यादा की और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सितंबर में थोक महंगाई दर अगस्त के 9.92 प्रतिशत से बढ़कर 11. 39प्रतिशत हो गई, जिसका मुख्य कारण तेल की कीमतों में 57.32 प्रतिशत की भारी वृद्धि थी। आरबीआई प्रमुख संजय मल्होत्रा ने कहा कि भविष्य में दरों में बढ़ोतरी आर्थिक विकास और महंगाई के रुझानों पर निर्भर करेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि सितंबर में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा स्वीकार की गई कीमतों में बढ़ोतरी का, उपभोक्ताओं के लिए कीमतों और बिजली के बिलों पर कितना असर पड़ेगा?



त्यौहारी मौसम के दौरान आने वाली ये आर्थिक चुनौतियां उन छोटे व्यवसायों को प्रभावित कर सकती हैं, जो पूरी तरह से अपनी बिक्री पर निर्भर हैं। बढ़ती कीमतें मुनाफे के मार्जिन को कम कर सकती हैं, लेकिन ये हाथ से बनी वस्तुओं के महत्व को भी उजागर करती हैं। अनोखे और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद पेश करके, स्थानीय विक्रेता उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं जो असली और पारंपरिक चीजों की तलाश में हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं और घरेलू नीतियों ने भारत में महंगाई पर काफी असर डाला है। सितंबर 2023 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 6.2 प्रतिशत बताई, जो इसके 2–6प्रतिशत के लक्ष्य दायरे से अधिक है। यह वृद्धि मुख्य रूप से भोजन, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की ऊंची कीमतों के कारण हुई है, जिसमें खाद्य महंगाई दर लगभग 7. 8 प्रतिशत रही है। हाल ही में उठाए गए कदमों में खाना पकाने की गैस और अनाज जैसी आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स में कटौती और सब्सिडी देना शामिल है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने त्यौहारी मौसम से पहले आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने और महंगाई को कम करने के लिए खरीद के प्रयासों को तेज कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2026–27 के लिए 7.1 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाया है, जिसमें खुदरा महंगाई दर 5.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। हालांकि, साल की आखिरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर) में महंगाई बढ़कर 6 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। आरबीआई प्रमुख ने जोर देकर कहा कि भले ही अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन बढ़ती महंगाई अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। खुदरा विक्रेता इन आर्थिक रुझानों के अनुसार खुद को ढाल रहे हैं। वे आवश्यक वस्तुओं पर बंडल डील और छूट देकर ग्राहकों को पैसे की सही कीमत देने पर जोर दे रहे हैं। इस रणनीति से मध्यम श्रेणी के उत्पादों की बिक्री में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग में कमी आई है। स्थानीय बाजार और कारीगर इन आर्थिक चुनौतियों के बीच खुद को ढाल रहे हैं। उनके लिए त्यौहार का समय उनकी सालाना कमाई का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा होता है। इंस्टाग्राम और पिनटेरेस्ट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे सुझावों से भरे पड़े हैं, जो इस दौरान लोगों को रचनात्मकता और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सरकार ने खाना पकाने की गैस और अनाज जैसी जरूरी चीजों पर टैक्स में कटौती और सब्सिडी लागू की है। भारतीय खाद्य निगम ने भी आपूर्ति को लगातार बनाए रखने के लिए खरीद के प्रयासों को बढ़ाया है। इन उपायों का उद्देश्य त्यौहारी मौसम के करीब आते ही महंगाई को नियंत्रित करना है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ग्राहकों को कीमतों के रुझानों के बारे में जागरूक करने और खरीदारी के लिए दिशा–निर्देश देने के लिए अभियान शुरू किए हैं, ताकि आर्थिक चुनौतियां त्यौहारों की खुशियों पर भारी न पड़ें। शिपिंग में रुकावटों, उर्वरकों की ऊंची लागत और श्अलनीनोश के प्रभावों के कारण 2027 तक वैश्विक खाद्य महंगाई बढ़ने की आशंका है। इंडोनेशियाई चावल और भारतीय चीनी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं, और मिश्र में ब्रेड की कीमतों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। स्टॉक में कमी और आयात बढ़ने के कारण कीमतों में और उछाल आने का अनुमान है। अपनी ताजा रिपोर्ट में, आरबीआई ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच महंगाई दर में अंतर को रेखांकित किया है, जिसमें ग्रामीण इलाकों में महंगाई अधिक देखी गई है। इन समस्याओं से निपटने के लिए, सब्जियों जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के भंडारण, प्रसंस्करण और वितरण के बुनियादी ढांचे में सुधार करना जरूरी है। इसके अलावा, घरेलू स्तर पर तिलहन का उत्पादन बढ़ाकर खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता कम करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि, लॉजिस्टिक्स और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में मौजूद बाधाओं को दूर करना आवश्यक है। औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने से अनौपचारिक क्षेत्र में कीमतों के उतार–चढ़ाव को कम करने में भी मदद मिल सकती है। इन चुनौतियों के बावजूद, त्यौहारों के मौसम में उपभोक्ता और व्यवसाय लगातार लचीलापन और रचनात्मकता दिखा रहे हैं।

महंगाई पर नियंत्रण और आर्थिक विकास की चुनौती

अरुण कुमार डनायक

अर्थव्यवस्था की चर्चा होते ही महंगाई, ब्याज दर, जीडीपी, राजकोषीय घाटा और आर्थिक विकास जैसे शब्द सामने आने लगते हैं। सरकार और रिजर्व बैंक अपनी राजकोषीय व मौद्रिक नीतियों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों और महंगाई को प्रभावित करते हैं। इन निर्णयों का आम नागरिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? महंगाई बढ़ने पर ब्याज दरें क्यों बढ़ाई जाती हैं और क्या केवल मौद्रिक उपायों से महंगाई नियंत्रित हो सकती है? ये प्रश्न आर्थिक नीतियों के आकलन में सहायक हैं। अर्थव्यवस्था किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों, व्यापारियों और निवेशकों के निर्णयों से संचालित होती है। लोग कितना खर्च, बचत और निवेश करेंगे तथा सरकार किन क्षेत्रों पर व्यय करेगी, इन सबका प्रभाव आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है। सरकार और केंद्रीय बैंक की नीतियों का उद्देश्य महंगाई पर नियंत्रण, निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन तथा टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना है। महंगाई का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि होना है। जब खाद्य सामग्री और रोजमर्रा की वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें आमदनी की तुलना में तेजी से बढ़ती हैं, तो लोगों की वास्तविक क्रयशक्ति घट जाती है। महंगाई की दर में गिरावट का अर्थ कीमतों का कम होना नहीं, बल्कि उनके बढ़ने की गति धीमी पड़ना हैय इसलिए इससे आम लोगों को वास्तविक राहत मिलना जरूरी नहीं है। महंगाई कई कारणों से बढ़ सकती है। कभी बढ़ती मांग कीमतों पर दबाव डालती है, तो कभी पेट्रोलियम, ऊर्जा, परिवहन, मजदूरी और कच्चे माल की बढ़ती लागत उत्पादन को महंगा बना देती है। सूखा, बाढ़, युद्ध और वैश्विक आपूर्ति व्यवधान भी कीमतें बढ़ा सकते हैं। इसलिए महंगाई को किसी एक कारण या केवल सरकारी नीतियों का परिणाम मानना उचित नहीं है। महंगाई का प्रसार तब चिंता का विषय बनता है, जब मूल्य–वृद्धि कुछ वस्तुओं तक सीमित न रहकर अर्थव्यवस्था के व्यापक हिस्से में फैलने लगती है। महंगाई के प्रभाव को समझने के लिए अर्थशास्त्री उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले बदलाव का आकलन करते हैं। महंगाई को नियंत्रित करने में भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीय भूमिका होती है। उसका प्रमुख साधन रेपो दर है, जिसके माध्यम से वह बैंकों के लिए धन की लागत को प्रभावित करता है। रेपो दर बढ़ने पर व्यक्तिगत ऋणों की ईएमआई बढ़ सकती है और कारोबार के लिए ऋण महंगा हो सकता है। इससे परिवारों और कंपनियों के खर्च तथा निवेश में कमी आ सकती है, जिससे महंगाई नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ब्याज दरों का प्रभाव सभी पर एक समान और तत्काल नहीं पड़ता। ऋण महंगा होने से मांग घट सकती है, जबकि बचत और सावधि जमा पर मिलने वाला प्रतिफल बढ़ सकता है। फिर भी यदि महंगाई का प्रमुख कारण तेल, खाद्यान्न या अन्य वस्तुओं की आपूर्ति में कमी हो, तो केवल ब्याज दरें बढ़ाना पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में अत्यधिक सख्ती निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास को भी प्रभावित कर सकती है। रेपो दर के अलावा आरबीआई नकद आरक्षित अनुपात के माध्यम से बैंकों की जमा का वह हिस्सा निर्धारित करता है, जिसे नकदी के रूप में रखना अनिवार्य है। वैधानिक तरलता अनुपात के तहत बैंकों को जमा का एक निर्धारित हिस्सा नकदी, सोने और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है। खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद–बिक्री से भी आरबीआई बैंकिंग प्रणाली में धन और ऋण प्रवाह को प्रभावित करता है। वह विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर रुपये की अस्थिरता कम करने का प्रयास भी करता है, हालांकि इससे वैश्विक तेल कीमतों या बाहरी आपूर्ति संकटों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मौद्रिक नीति की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि लोग और व्यवसाय भविष्य को कैसे देखते हैं। यदि उन्हें लगातार महंगाई बढ़ने की आशंका हो, तो वे अपने खर्च, वेतन और मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णय उसी अनुसार लेने लगते हैं, जिससे महंगाई और बढ़ सकती है। इसके विपरीत, स्थिर कीमतों का विश्वास आर्थिक व्यवहार को संतुलित बनाता है। इसलिए रिजर्व बैंक के लिए स्पष्ट संवाद और नीतिगत विश्वसनीयता भी ब्याज दरों जितनी ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक सुस्ती के दौर में सरकार सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर रोजगार, आय और मांग को प्रोत्साहन दे सकती है। इसके विपरीत, व्यापक महंगाई की स्थिति में वह करों, सरकारी व्यय और सब्सिडी में बदलाव करके मांग तथा कीमतों के दबाव को संतुलित करने का प्रयास करती है। आयकर में राहत से लोगों की उपलब्ध आय बढ़ सकती है, जबकि जीएसटी में कटौती से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी आ सकती है। हालांकि, इन उपायों का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि राहत किस सीमा तक उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। साथ ही, करों में कटौती से सरकारी राजस्व घट सकता है, इसलिए सरकार को आम लोगों को राहत देने और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ता है। सरकारी खर्च विकास और जनकल्याण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण साधन है। बुनियादी ढांचे, कृषि, कौशल विकास और स्वास्थ्य पर निवेश से उत्पादकता, रोजगार और दीर्घकालीन विकास को बढ़ावा मिल सकता है। वहीं, कमजोर तबकों तक सामाजिक सहायता समय पर और पारदर्शी ढंग से पहुंचने से उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होती है। महंगाई से निपटने के लिए सरकार अल्पकाल में आपूर्ति सुधारने हेतु सार्वजनिक भंडार से अनाज जारी करने, आयात सुगम बनाने, जमाखोरी पर रोक लगाने और राज्यों के साथ समन्वय जैसे कदम उठा सकती है। वहीं, दीर्घकाल में सिंचाई, भंडारण, शीतगृह, खाद्य प्रसंस्करण और आपूर्ति शृंखला में निवेश से उत्पादन और उपलब्धता बढ़ाकर मूल्य दबाव को स्थायी रूप से कम किया जा सकता है। भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देश में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों और रुपये के मूल्य में उतार–चढ़ाव से आयात लागत तथा महंगाई प्रभावित होती है। इस निर्भरता को कम करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देना और निर्यात क्षमता को मजबूत करना आवश्यक है। आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता के लिए सरकार, रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों के बीच समन्वय तथा कारोबारियों का विश्वास महत्वपूर्ण है। वाणिज्यिक बैंक जमा और ऋण नीतियों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं।

श्जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने, दंडात्मक प्रावधानों में उचित नरमी बरतने और कर अनुपालन को अधिक पारदर्शी बनाने जैसे कदम कारोबारी गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के बीच केवल ब्याज दरों में बदलाव या कर राहत पर्याप्त नहीं है। महंगाई पर नियंत्रण, उत्पादक निवेश, रोजगार सृजन और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने वाली समन्वित नीति ही व्यापक आर्थिक हितों की पूर्ति कर सकती है। अंततरू आर्थिक नीतियों की सफलता का आकलन आम नागरिक की क्रयशक्ति, रोजगार के अवसरों और जीवन–स्तर में सुधार से किया जाना चाहिए।

कार्तिक मास: पुण्य का सागर, पर जातक के लिए शांति आवश्यक: आचार्य पदमाकर मिश्र



स्वाभिमान जागरण, देवरिया – धर्म–ज्योतिष विशेष

सनातन धर्म में कार्तिक मास को सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है – रोगापहं पातकनाशकृत्परं सद्बुद्धिदं पुत्रधनादिसाधकम्। मुक्तेर्निदानं नहि कार्तिकव्रताद् विष्णुप्रियादन्यदिहास्ति भूतले अर्थात कार्तिक व्रत रोगों का नाश करने वाला, पापों को हरने वाला, सद्बुद्धि, पुत्र और धन को देने वाला तथा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। भगवान विष्णु को यह मास अत्यंत प्रिय है। ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी से कहा है – "न कार्तिकसमो मासो न कृतेन समं युगं, न वेदं सदृशं शास्त्रं न तीर्थं गंगया समं।" अर्थात कार्तिक के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। इस मास में गंगा स्नान और दीपदान करने से मनुष्य को आरोग्य, ज्ञान, संस्कार, धन और मोक्ष की प्राप्ति होती है। परन्तु ज्योतिषीय दृष्टिकोण भी जानना आवश्यक है – ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक मास में जन्म लेना माता और पुत्र दोनों के लिए कष्टकारी माना जाता है। इसका कारण यह है कि इस मास में सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गोचर करता है। सूर्य आत्मा और ऊर्जा का कारक है। सूर्य के निर्बल होने से कार्तिक में जन्म लेने वाले जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, ऊर्जा की कमी, पाचन तंत्र में विकार, हड्डियों में कमजोरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, प्रशासनिक कार्यों में बाधा, पदोन्नति में रुकावट तथा पिता और ससुर पक्ष से संबंधों में तनाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसी दोष के निवारण के लिए हमारे शास्त्रों में कार्तिक स्त्री प्रसूता शांति का विधान बताया गया है। शांति विधान – मेरा सभी माता–पिता से निवेदन है कि कार्तिक मास में जन्मे बालक–बालिका की शांति अवश्य कराएं। शांति में सर्वप्रथम गणेशादि पूजन, कलश स्थापना, ब्रह्मा–विष्णु–महेश का पूजन, सूर्यादि ग्रह पूजन, आयु के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र का जप, तिल, घृत और बिल्व पत्रों से दशांश हवन, दर्भयुक्त जल से अभिषेक और छायापात्र दान करना चाहिए। तत्पश्चात माता और पुत्र या पुत्री को कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा या किसी पवित्र तीर्थ में स्नान कर दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से कार्तिक जन्म का समस्त दोष शांत हो जाता है और जातक को सुख–समृद्धि प्राप्त होती है।

स्रोत हो सुरक्षित

पत्रकारिता के पेशे में मीडियाकर्मी का नैतिक दायित्व होता है कि वह किसी खोजपूर्ण खबर में सहायक स्रोत की सुरक्षा और विश्वास को कायम रख सके। अपने गोपनीय स्रोत की सुरक्षा का वायदा सुनिश्चित करना महज एक पेशेवर शिष्टाचार नहीं है, सही मायने में यह खोजी पत्रकारिता की बुनियाद भी है। यदि जनहित के लिए महत्वपूर्ण गोपनीय सूचना देने वाले का भरोसा खत्म होगा तो भ्रष्टाचार और जन–विरोधी कार्यों में लिप्त लोगों के गलत कार्यों का खुलासा करने वाले लोग आगे नहीं आएंगे। यानी व्हिसलब्लोअर किसी गंभीर कदाचार आदि के मुद्दे पर चुप्पी साध सकते हैं। यदि सूचना स्रोत की गोपनीयता भंग होती है, तो गलत कामों के वास्तविक तथ्य कभी भी सामने नहीं आ पाएंगे। बहुत संभव है कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र के हित में, जनता को जानने योग्य जरूरी जानकारी से वंचित होना पड़ सकता है। इस विषय के महत्व की गंभीरता के चलते ही देश के सर्वोच्च न्यायालय में देश के 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट' यानी डीपीडीपी को चुनौती दी गई। जिसने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को सार्वजनिक विमर्श में ला दिया है। यही वजह है कि डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन ने चेताया है कि इस कानून के प्रावधान किसी मीडियाकर्मी के गोपनीय स्रोतों को सार्वजनिक कर सकते हैं। जो स्वतंत्र समाचार संग्रहण और इस बाबत जांच–पड़ताल में बाधक साबित हो सकते हैं। इस समस्या का चिंताजनक पहलू यह भी कि सरकार के पास नागरिकों की निजी सूचना एकत्र करने वाली संस्थाओं से जानकारी हासिल करने के अधिकार हैं। जिससे उन लोगों की पहचान उजागर हो सकती है जो भरोसे के चलते ही पत्रकारों के पास आते हैं। निश्चय ही किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी बंदिशें लादने से मीडिया की स्वतंत्रता पर आंच आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इस संदर्भ में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद, कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बाबत जवाब मांगा है। उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 17 नवंबर तय की है। इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि आज की तेजी से डिजिटल होती दुनिया में निजता की सुरक्षा बनाये रखना बहुत आवश्यक है। निस्संदेह, नागरिकों को उनकी निजी जानकारी का दुरुपयोग होने से बचाया जाना बेहद जरूरी है। साथ ही यह भी जरूरी है कि निजता की सुरक्षा के लिये बनाया गया कोई कानून प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ताधीशों के लिये ऐसा जरिया नहीं बन जाना चाहिए, जो तथ्यों की तलाश व जांच–पड़ताल में बाधक बने। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि शासन–प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और कॉर्पोरेट में होने वाली गड़बड़ियों की पड़ताल अकसर ऐसे लोगों पर निर्भर करती है, जो बड़े निजी जोखिम को उठाकर भी वास्तविक तथ्य देश व समाज हित में बताने को राजी होते हैं। ऐसे में यदि पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना उनकी पहचान उजागर हो जाती है तो पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर इसका व्यापक प्रतिकूल असर पड़ सकता है। फिर जोखिम उठाकर सूचना देने वाले लोग, ऐसा करने से कतराने लगते हैं। इससे जुड़ा एक वास्तविक पहलू यह भी है कि अपने स्रोत की सुरक्षा का अधिकार पत्रकारों को बिना किसी जवाबदेही के काम करने की छूट नहीं देता है। लेकिन यदि कोई अपवाद सामने आता है तो उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। उसका सार्वजनिक होना बेहद जरूरी है। वहीं उसकी स्वतंत्र न्यायिक निगरानी होनी चाहिए। ऐसे में न्यूजरूम के रिकॉर्ड तक बिना किसी रोक–टोक के पहुंच होने से, स्रोत की सुरक्षा और जनता के जानने के अधिकार को नुकसान पहुंच सकता है। देश की शीर्ष अदालत से उम्मीद की जाती है कि बहुत सावधानी से निजता और प्रेस की आजादी के बीच संतुलन बनाया जाए। यदि वास्तविक पत्रकारिता के कार्यों के लिये स्पष्ट छूट दी जाती है, और साथ ही गोपनीय स्रोत के उजागर होने से रोकने के लिये सुरक्षा उपाय भी हों, तो इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कानून जनहित से जुड़ी रिपोर्टिंग में बाधा न बनेगा।

सीएम योगी से सिंगापुर के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की

योगी बोले सिंगापुर की तकनीक और यूपी का सामर्थ्य, मिलकर लिखेंगे नई इबारत

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख ग्रोथ इंजन बनाने और 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ में सिंगापुर के शीर्ष उद्योगपतियों एवं निवेशकों के 14 सदस्यीय उच्चस्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तृत चर्चा की। सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में लॉजिस्टिक्स, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी, अर्बन प्लानिंग और हॉस्पिटैलिटी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में बड़े निवेश की इच्छा व्यक्त की। यह प्रतिनिधिमंडल फरवरी में मुख्यमंत्री की सिंगापुर यात्रा के बाद अब उत्तर प्रदेश के दौरे पर आया है। प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक सिंगापुर के निर्माता स्वर्गीय ली कुआन यू के विजन ने दुनिया को दिखाया कि किसी देश की वैश्विक पहचान उसके भौगोलिक आकार से अधिक उसकी दृष्टि, कार्यक्षमता और संसाधनों के कुशल उपयोग से बनती है। उन्होंने कहा कि विगत 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत फ्रैजाइल अर्थव्यवस्था की स्थिति से निकलकर दुनिया की अग्रणी और सशक्त अर्थव्यवस्थाओं में स्थापित हुआ है। इसी प्रकार, पिछले साढ़े नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश भी बीमा छवि से बाहर निकलकर देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है। प्रदेश की जीडीपी, वार्षिक बजट और प्रति व्यक्ति आय तीन गुना हुई है। वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी भी तीन गुना बढ़ी है। बिना जनता पर कोई नया कर लगाए उत्तर प्रदेश निरंतर रेवेन्यू–सरप्लस राज्य बना हुआ है। फरवरी 2026 में सिंगापुर यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति श्री थर्मन षणमुगरत्नम जी और प्रधानमंत्री श्री लॉरेंस वोंग जी से हुई मुलाकातों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उस दौरान लगभग ध्60,000 करोड़ के निवेश समझौतों पर सहमति बनी थी। सिंगापुर रोडशो के दौरान राज्य सरकार ने निवेशकों को सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीडश का जो भरोसा दिया था, प्रदेश आज भी उसी कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब लक्ष्य निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर उत्पादन शुरू कराने का है। एमओयू से मैन्युफैक्चरिंग और ग्राउंडब्रेकिंग से प्रोडक्शन तक की पूरी प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और हर स्तर



पर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के समक्ष जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट समर्पित शसिंगापुर सिटी और हाई–टेक इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के संगम तथा विश्वस्तरीय एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जुड़ा यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए उत्तर भारत का प्रमुख सप्लाई चेन हब बनने की क्षमता रखता है। औद्योगिक निवेश के लिए प्रदेश में 75 हजार एकड़ से अधिक का लैंड बैंक उपलब्ध है और 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। वहीं, लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट में स्थापित यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के छह स्ट्रैटेजिक नोड्स को 35 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। साझेदारी को ठोस परिणामों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ने छह प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया। इनमें जेवर, एक्सप्रेसवे और फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग का विकास, सेमीकंडक्टर फैब यूनिट और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी हाई–टेक मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विसेज एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन, वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर रिसाइक्लिंग जैसी क्लीन टेक्नोलॉजी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश के कुल मोबाइल उत्पादन का लगभग 55 प्रतिशत और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का 60 प्रतिशत निर्माण उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उन्होंने प्रदेश की कृषि क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की श्फूड बास्केट्श के रूप में उत्तर प्रदेश का योगदान महत्वपूर्ण है। प्रदेश में 21: खाद्यान्न उत्पादन और सिंगापुर के हाई–क्वालिटी फूड पैकेजिंग एवं एक्सपोर्ट मॉडल के बीच साझेदारी की व्यापक संभावनाएं हैं।

मिर्जापुर का जरगो बांध पानी से लबालब, किसान गदगद

दशकों का इंतजार खत्म, जरगो बांध तक पहुंचा 229 क्यूसेक पानी

15 हजार किसानों को हो रहा फायदा, 6,300 हेक्टेयर खेतों को सिंचाई की सुविधा

संवाददाता

लखनऊ। योगी सरकार प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने और किसानों तक पर्याप्त पानी पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मीरजापुर के जरगो बांध के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। पिछले कई दशकों से खराब पड़े मेजा–जरगो लिंक नहर के दोनों अंडर स्लूस गेटों की मरम्मत और पुनर्स्थापन के बाद बांध में पानी की आपूर्ति सुचारु हुई है। करीब 30 वर्षों बाद जरगो बांध के पानी से लबालब होने की स्थिति ने क्षेत्र के किसानों के लिए नई उम्मीद जगाई है। वर्तमान में मेजा–जरगो लिंक नहर के माध्यम से बांध में 229 क्यूसेक पानी की आपूर्ति की जा रही है।प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन अनिल गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने और उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। मेजा–जरगो लिंक नहर के गेटों की मरम्मत इस दिशा में महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ इंजीनियरिंग के समन्वय से वर्षों पुरानी समस्या का समाधान किया गया। उन्होंने बताया कि मेजा–जरगो लिंक नहर मीरजापुर की कृषि सिंचाई व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके माध्यम से विभिन्न जलाशयों और नहरों को जोड़कर जरगो बांध तक पानी पहुंचाया जाता है। लगभग 71.130 किलोमीटर लंबी और 580 क्यूसेक क्षमता वाली यह नहर क्षेत्र की कृषि भूमि की सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नहर के हेड पर स्थापित दो अंडर स्लूस गेट लंबे समय से खराब थे। इनके जरिए लगातार पानी का रिसाव होने से जल प्रबंधन प्रभावित हो रहा था। इन दोनों गेटों से करीब 150 क्यूसेक पानी लगातार व्यर्थ बह रहा था। इसके चलते न केवल उपलब्ध सिंचाई जल का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा था, बल्कि नहर के आगे के हिस्से में गाद की सफाई और जल प्रवाह को नियंत्रित करना भी मुश्किल हो गया था। वहीं रिसाव के कारण नहर के डाउनस्ट्रीम में लगभग 10 किलोमीटर तक जमी सिल्ट की सफाई नहीं हो पा रही थी। मुख्य अभियंता यांत्रिक उपेंद्र सिंह ने बताया कि गेटों की मरम्मत सामान्य इंजीनियरिंग कार्य नहीं था। गेट जल सतह से लगभग 15 मीटर नीचे स्थित थे, जहां पानी का दबाव वायुमंडलीय दबाव से करीब 2.5 गुना था। अत्यधिक रिसाव के कारण पानी के भीतर सीधे निरीक्षण करना गोताखोरों के लिए भी जोखिम भरा था। गेटों के संचालन से जुड़े हिस्से क्षतिग्रस्त थे और रबर सील तथा दीवार के बीच बने अंतर से पानी लगातार रिस रहा था। इससे निपटने के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की सिंचाई कार्यशाला खंड, बरेली की टीम ने चरणबद्ध रणनीति अपनाई। सबसे पहले विशेष सामग्री की मदद से रिसाव को अस्थायी रूप से रोका गया, जिससे पानी के भीतर काम करने की परिस्थितियां सुरक्षित बनाई जा सकें। इसके बाद आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल को 4के वीडियो कैमरे के साथ पानी में उतारा गया। इसके माध्यम से गेटों के दोनों ओर का निरीक्षण किया गया और क्षतिग्रस्त हिस्सों, रबर सील के बीच के अंतर तथा दीवार में मौजूद छेदों की पहचान की गई।

हर माह एक लाख प्रशिक्षण का लक्ष्य-केशव

प्रशिक्षण की गुणवत्ता से कार्यदक्षता तक ग्राम्य विकास संस्थान की व्यवस्था में सुधार के निर्देश

संवाददाता

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकारियों, कर्मचारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीण विकास से जुड़े कार्मिकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए मासिक एक लाख प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। जिला स्तर से लेकर संस्थान मुख्यालय तक नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। प्रशिक्षण की गुणवत्ता, विषयवस्तु और उपयोगिता में निरंतर सुधार करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रशिक्षण का लाभ संबंधित कार्मिकों के कार्य व्यवहार और जनसेवा की गुणवत्ता में दिखाई दे।श्री मौर्य ने अप्रैल से सितम्बर तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति, गुणवत्ता, सुधार और कार्यदक्षता की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता और उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप मासिक प्रशिक्षण रोस्टर तैयार किया जाए। प्रशिक्षणार्थियों को आवास, भोजन, शिक्षण सामग्री सहित आवश्यक सुविधाएं समय से उपलब्ध कराई जाएं। प्रशिक्षकों एवं शिक्षकों के मानदेय का भुगतान निर्धारित समय पर सुनिश्चित किया जाए तथा उन्हें अनुमन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की देरी न हो। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि इनसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता, कार्यशैली और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सुधार होना चाहिए। महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान सौरव बाबू ने बताया की दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान अंतर्गत 17 मंडल स्तरीय क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान तथा 33 जनपद स्तरीय जिला ग्राम्य विकास संस्थान संचालित हैं। संस्थान का उद्देश्य आधारभूत एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन का कौशल उन्नयन करना तथा ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन से जुड़े कार्मिकों की क्षमता बढ़ाना है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक राज्य ग्राम्य विकास संस्थान में 138 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 5,032 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिला ग्राम्य विकास संस्थानों में 1,15,971 प्रतिभागियों की प्रशिक्षण प्रगति दर्ज की गई। नवनियुक्त खंड विकास अधिकारियों के 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक सत्र में 57 अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम, 2025 विषयक 44 प्रशिक्षण सत्रों में 990 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।उत्तर प्रदेश समग्र शिक्षा विभाग के लर्निंग बाई डूइंग एवं आईसीटी से संबंधित 24 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 1,172 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। जनगणना–2027 के द्वितीय चरण के लिए आठ सत्रों में 332 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए आयोजित 3,334 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,03,905 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत संस्थान एवं अधीनस्थ संस्थानों के लगभग 602 पंजीकृत अधिकारियों और कर्मचारियों ने 28,955 ऑनलाइन पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे किए। श्री मौर्य ने कहा कि मासिक एक लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्यालय, क्षेत्रीय एवं जिला स्तर पर समन्वय बनाकर कार्य किया जाए। इससे ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और जनसामान्य को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

जीत के जश्न पर अखिलेश की नसीहत, जुलूस न निकालें, भाजपा बिगाड़ सकती है छवि, आकाश अग्रवाल के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी के विजयी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जीत का जश्न सोशल मीडिया के जरिए मनाया जाए और कोई हो–हल्ला या जुलूस न निकाला जाए। अखिलेश यादव ने आशंका जताई कि विजयी जुलूस निकालने पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) साजिश करके सपा की छवि बिगाड़ सकती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव का ध्यान रखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जीत की खुशी शांतिपूर्ण तरीके से लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश न कर सके और सपा पर हुड़दंग करने का आरोप न लगे। सपा प्रमुख अखिलेश ने कहा कि पार्टी सभी विजयी एमएलसी का अभिनंदन करेगी। संभव हुआ तो



वह स्वयं उनके क्षेत्रों में जाकर सम्मान करेंगे। उन्होंने विजयी उम्मीदवारों से उन कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और शुभचिंतकों की सूची तैयार करने को कहा, जिन्होंने चुनाव में उनका समर्थन और सहयोग किया है। अखिलेश ने कहा कि जीत में योगदान देने वाले सभी लोगों का भी सम्मान किया जाएगा। अखिलेश यादव ने आगरा में सपा के शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और उसके सहयोगियों के व्यवहार से अग्रहरि समाज आहत है। अखिलेश ने कहा कि इस घटना के बाद समाज के लोग खुद को अपमानित और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।उन्होंने अपने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि अब इसमें (ए) का मतलब अग्रवाल–अग्रवंशी भी है। अखिलेश ने कहा, जो पीड़ित, वो पीडीए ही उनका नारा है। सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि अग्रवाल समाज के साथ आने से पार्टी का जनाधार और मनोबल बढ़ा है। उन्होंने कहा कि शैक्षिक और व्यावसायिक रूप से सशक्त इस समाज का समर्थन पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। अखिलेश ने अपने राजनीतिक संदेश में भाजपा पर निशाना साधते हुए पीडीए की लड़ाई को 5 प्रतिशत भाजपाइयों बनाम 95 प्रतिशत पीडीए की लड़ाई बताया। पोस्ट के अंत में अखिलेश यादव ने समाजवादी चिंतक डॉ. राम मनोहर लोहिया के आदर्शों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लोहिया के आदर्श पहले भी पार्टी के लिए प्रकाश स्तंभ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे।

सुमन उपाध्याय को डॉ. अंबेडकर पुरस्कार मिला

संवाददाता

लखनऊ। सरोजनीनगर स्थित शांति नगर के सेंट एंजेल्स कॉलेज में बुधवार को संस्थापक निदेशक सुमन उपाध्याय के सम्मान में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। उन्हें 24 अक्टूबर 2026 को चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय के गोल्डन जुबली हॉल में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स (टीएसजी) कॉन्फ्रेंस–2026 के दौरान डॉ. बीआर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार–2026 से सम्मानित किया गया था। कॉलेज परिवार ने इस उपलब्धि पर सुमन उपाध्याय का स्वागत कर उन्हें बधाई दी। कॉलेज प्रबंधक वीरेंद्र उपाध्याय ने उन्हें सम्मानित किया। प्रधानाचार्या शालिनी चतुर्वेदी ने भी शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में सुमन उपाध्याय का योगदान प्रेरणादायी है। उनके तीन दशक के समर्पण, नेतृत्व और सामाजिक कार्यों को इस सम्मान का प्रमुख आधार बताया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने बधाई गीत के माध्यम से उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। कक्षा नौ के विद्यार्थियों ने अपने संदेश में उनके नेतृत्व और निरंतर समर्पण की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुमन उपाध्याय की यात्रा आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा और समाजसेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। सुमन उपाध्याय ने बताया कि टीएसजी कॉन्फ्रेंस–2026 का उद्देश्य पारंपरिक खेलों का संरक्षण, संवर्धन और प्रचार–प्रसार करना था। इसके साथ विभिन्न खेल संगठनों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। सम्मेलन में नशा मुक्त भारत अभियान और स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करने जैसे सामाजिक विषयों पर चर्चा हुई। सुमन उपाध्याय ने कॉलेज स्टाफ का आभार जताते हुए बताया कि पंजाब विश्वविद्यालय के गोल्डन जुबली हॉल में 20 लोगों को पुरस्कार दिया गया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का विषय उनके दिल को छू गया। शांति की स्थापना, खेलों का विकास, सामाजिक–सांस्कृतिक प्रगति और बेहतर स्वास्थ्य के लिए देश को नशामुक्त बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बच्चों को नशे और गलत आदतों से दूर रखकर ही उन्हें सही दिशा दी जा सकती है। यह पुरस्कार उनके लिए तभी सार्थक होगा, जब वे बच्चों को नशे से दूर रहने और बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकें। कार्यक्रम के दौरान राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कॉलेज के विद्यार्थियों तनमय वर्मा और परी तिवारी को सम्मानित किया गया। उनकी उपलब्धि पर विद्यालय परिवार ने हर्ष व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

यूपी एमएलसी चुनाव में बीजेपी का दबदबा, 6 सीटों के नतीजे घोषितय 4 पर भाजपा और 2 पर सपा को जीत

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 11 शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव के लिए जारी मतगणना में अब तक छह सीट के परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित किए गए हैं, जिनमें से चार सीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और दो पर समाजवादी पार्टी (सपा) ने जीत हासिल की है। वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की प्रतिष्ठित सीट पर सपा के लाल बिहारी यादव ने जीत हासिल की है। राज्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से बुधवार को जारी परिणाम के अनुसार, मेरठ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के दिनेश कुमार गोयल, लखनऊ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उमेश द्विवेदी, वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सपा के लाल बिहारी यादव, आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सपा के डॉ. आकाश अग्रवाल, मेरठ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के श्रीचंदर शर्मा और बरेली–मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के डॉ. हरि सिंह ढिल्लो ने जीत हासिल की है। वाराणसी खंड शिक्षक क्षेत्र की



प्रतिष्ठित सीट पर सपा प्रत्याशी लाल बिहारी यादव ने काफी विवाद और आरोप–प्रत्यारोप के बीच जीत हासिल की। यादव ने परिणाम घोषित होने से पहले ही अपनी जीत का दावा करते हुए प्रशासन पर जीत की आधिकारिक घोषणा करने में देरी का आरोप लगाया। चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने वाराणसी शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना को लेकर जिला प्रशासन पर सवाल उठाए थे और कहा था कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सपा प्रत्याशी लाल बिहारी यादव चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन परिणाम घोषित नहीं कर रहा। उन्होंने कहा था कि यादव की जीत के बावजूद करीब छह घंटे तक परिणाम की आधिकारिक घोषणा नहीं किए जाने से संदेह पैदा होता है। वाराणसी खंड स्नातक सीट पर सपा के आशुतोष सिन्हा, इलाहाबाद–झांसी खंड स्नातक सीट पर सपा के डॉ. मानसिंह यादव और लखनऊ खंड स्नातक सीट पर सपा की कांति सिंह ने मजबूत बढ़त बना रखी है। वहीं, आगरा–अलीगढ़ खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह जीत की ओर बढ़ रहे हैं। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल 11 विधान परिषद सीट के लिए मतगणना मंगलवार सुबह आठ बजे शुरू हुई थी। इससे पहले, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्एक्सश पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें सपा प्रत्याशी अग्रवाल फटा कुर्ता पहने दिखाई दे रहे हैं और उनके समर्थक उनके साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। यादव ने पोस्ट में कहा, अब भाजपा खुद ही बताए कि आगरा से जीतते हुए सपा के एमएलसी प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल के साथ उसके लोगों द्वारा किया गया यह व्यवहार कितना जायज है। उन्होंने निर्वाचन आयोग के साथ–साथ उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति से भी मामले का तत्काल संज्ञान लेने का अनुरोध किया और प्रशासन से अग्रवाल को जीत का प्रमाणपत्र तुरंत देने का आग्रह किया। वहीं, गोरखपुर–फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने अंतिम चरण की मतगणना के बाद अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एवं निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव पर बढ़त बना रखी है। इस सीट पर मतगणना के दौरान मतों की संख्या में अंतर और मतगणना प्रक्रिया को लेकर विवाद हुआ। मऊ के एक बूथ की मतपेटी में दर्ज संख्या से 52 मत अधिक मिलने पर प्रत्याशियों ने आपत्ति जताई। इसके अलावा, एक प्रत्याशी की शिकायत के बाद अयोध्या के अपर आयुक्त अजय सैनी को मतगणना ड्यूटी से हटा दिया गया। हालांकि, प्रशासन ने कहा कि मतगणना नियमानुसार कराई जा रही है।

बीजेपी में दूसरे दलों से आए नेताओं को तवज्जो से नाराजगी,आरएसएस ने अंदरूनी कलह दूर करने में जुटा

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हैं। बमुश्किल चुनाव में 4 महीने का समय बचा है और इससे पहले सत्ताधारी भाजपा ने पार्टी की अंदरूनी कलह को दूर करने की कवायद शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के भीतर मतभेदों को दूर करने और कार्यकर्ताओं की नाराजगी कम करने के लिए फीडबैक एक्सरसाइज शुरू की है। बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं के बीच वाराणसी और सुल्तानपुर में संगठनात्मक बैठकें हुईं जिनमें पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी, संगठन में पदों के बंटवारे, प्रशासन में उनकी कथित अनदेखी और विपक्ष के आरोपों का जवाब देने में नेताओं की भूमिका पर चर्चा हुई।विधानपरिषद चुनाव के नतीजों में सपा के बेहतरीन प्रदर्शन ने बीजेपी की टेन्शन और बढ़ा दी है। बैठकों में ही यह तय हुआ कि इन मुद्दों से निपटने के लिए फीडबैक एक्सरसाइज शुरू की जाएगी। जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं में 'निराशा' है क्योंकि पार्टी लीडरशिप और राज्य प्रशासन के कुछ हिस्सों द्वारा उनकी कथित अनदेखी की जा रही है। सीनियर नेताओं ने जिले के पदाधिकारियों से कहा है कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर समाजवादी पार्टी के हमलों का मुकाबला करने के लिए काफी कुछ नहीं कर रहे हैं।बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 8 अक्टूबर को वाराणसी में काशी क्षेत्र के पुराने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी,बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश के सह–प्रभारी जगदीश पटेल मौजूद थे। एक नेता ने संगठन में पद और जिम्मेदारियां देने के पार्टी के मानदंडों पर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि दिल्ली और लखनऊ में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने वाले लोगों को संगठन में महत्वपूर्ण पद मिल जाते हैं, जबकि जमीन पर काम करने वाले पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है। एक नेता ने मौजूदा विधायकों की जगह नए चेहरों को मौका देने का सुझाव दिया। एक अन्य नेता ने कहा कि दूसरे दलों से आने वाले लोगों को विधानसभा चुनाव का टिकट देना या मंत्री बनाना राजनीतिक जरूरत हो सकती है, लेकिन उन्हें संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करने से पुराने कार्यकर्ताओं के लिए उनके साथ काम करना मुश्किल हो जाता है।14 और 15 अक्टूबर को वाराणसी में बीजेपी के विस्तारकों और काशी तथा गोरखपुर क्षेत्रों की विधानसभा सीटों के प्रभारियों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला हुई। काशी क्षेत्र की 71 और गोरखपुर क्षेत्र की 62 विधानसभा सीटों से जुड़े संगठनात्मक कामकाज पर चर्चा हुई। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं ने चिंता जताई कि विधायक समेत जिला स्तर के पदाधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के आरोपों का जवाब देने में पर्याप्त सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं।

योगी सरकार में गोवंश संरक्षण को मिला आर्थिक संबल

मंडी परिषद का बजट नौ वर्षों में 15 गुना से अधिक बढ़ा

निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण के लिए 69.16 करोड़ रुपये स्वीकृत

संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार निराश्रित गोवंश के संरक्षण, संवर्धन और बेहतर भरण–पोषण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने वित्तीय वर्ष 2026–27 में गोवंश संरक्षण के लिए 69.16 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसमें से 34.58 करोड़ रुपये की पहली किस्त उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग को जारी कर दी गई है। पिछले नौ वर्षों में इस मद में मंडी परिषद का वार्षिक वित्तीय प्रावधान 4.51 करोड़ रुपये से बढ़कर 69.16 करोड़ रुपये हो गया है, जो 15 गुने से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है।योगी सरकार की इस पहल के तहत कृषि मंडियों से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा निराश्रित गोवंश की सेवा और देखभाल पर खर्च किया जा रहा है। मंडी परिषद अपनी कुल आय का तीन प्रतिशत गोसेवा आयोग को उपलब्ध कराती है। इस धनराशि का उपयोग पंजीकृत गोशालाओं में संरक्षित गोवंश के लिए चारा, आश्रय, टीकाकरण, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में किया जाता है। इससे कृषि विपणन व्यवस्था से प्राप्त राजस्व को गोवंश संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व से जोड़ा गया है।गोवंश संरक्षण के लिए मंडी परिषद की ओर से दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि की प्रक्रिया वर्ष 2019 में तेज हुई, जब गोसेवा आयोग को अनुदान देने का प्रावधान दो प्रतिशत किया गया। इसके बाद वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंडी परिषद के संचालक मंडल ने परिषद की कुल आय का तीन प्रतिशत गोसेवा आयोग को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इस व्यवस्था के तहत अनुदान दो किस्तों में जारी किया जाता है। पहली किस्त में डेढ़ प्रतिशत राशि जारी होती है, जबकि शेष डेढ़ प्रतिशत राशि पहली किस्त के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद जारी की जाती है।मंडी परिषद के आंकड़े गोवंश संरक्षण के लिए बढ़ते वित्तीय सहयोग को दर्शाते हैं। वर्ष 2019–20 में 31.69 करोड़ रुपये, 2023–24 में 45.66 करोड़ रुपये, 2024–25 में 51.50 करोड़ रुपये और 2025–26 में 59.14 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 69.16 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह वृद्धि निराश्रित गोवंश के संरक्षण और गोशालाओं की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निराश्रित गोवंश का संरक्षण एवं संवर्धन प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

जनता की जमा-पूंजी पर डाका! पीएनबी में 35 करोड़ की कथित हेराफेरी, मैनेजर समेत 5 कर्मचारी सस्पेंड

संवाददाता
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की एक शाखा में खाताधारकों की रकम में कथित हेराफेरी का मामला सामने आया है। खाताधारकों ने बैंक में 35 करोड़ रुपये से अधिक की रकम के लेनदेन में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उनके खातों से उनकी जानकारी और सहमति के बिना पैसे दूसरे खातों में ट्रांसफर किए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंक प्रबंधन ने शाखा प्रबंधक समेत पांच कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। वहीं, पुलिस ने मामले में अभियोग पंजीकृत कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रकरण की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की टीम भी कर रही है। पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि, बीटा दो थाना क्षेत्र में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में खाताधारकों की रकम के लेनदेन को लेकर विवाद सामने आया। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके बैंक खातों से बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के रकम ट्रांसफर की गई। खातों में हुए कथित अनधिकृत लेनदेन की जानकारी मिलने के बाद खाताधारकों में नाराजगी फैल गई। इसके बाद प्रभावित लोगों ने मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की और पूरे प्रकरण की जांच कर कार्रवाई की मांग उठाई। बीटा दो क्षेत्र स्थित बैंक से जुड़े इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बैंक प्रबंधन ने भी खाताधारकों की शिकायतों के समाधान का भरोसा दिलाया है। वहीं, एंटी करप्शन टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच में कथित अनधिकृत ट्रांसफर, संबंधित बैंक खातों, लेनदेन के रिकॉर्ड और जिम्मेदार लोगों की भूमिका जैसे पहलुओं की पड़ताल महत्वपूर्ण होगी। इस मामले में 16 खाताधारकों ने बीटा दो थाना में शिकायत



दर्ज कराई है। शिकायतकर्ताओं ने बैंक खातों में 35 करोड़ रुपये से अधिक की कथित हेराफेरी का आरोप लगाया है। इतनी बड़ी रकम से खातों से कितनी राशि ट्रांसफर हुई और इस लेनदेन में किन लोगों की भूमिका रही, इन बिंदुओं पर जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। जुड़े आरोप सामने आने के बाद मामला गंभीर हो गया है। हालांकि, कथित हेराफेरी की कुल रकम, किन इस मामले के बाद बैंक प्रबंधन ने खाताधारकों की शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया है। साथ ही, प्रकरण के संबंध में शाखा प्रबंधक समेत कई कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। बैंक की ओर से उठाए गए इस कदम को मामले की जांच और शिकायतों के निस्तारण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है। हालांकि, कर्मचारियों का निलंबन अपने आप में आरोपों की पुष्टि नहीं करता। मामले में जिम्मेदारी तय होना जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगा। फिलहाल, खाताधारकों की निगाहें जांच के नतीजों और उनकी रकम के संबंध में होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं। अब देखना होगा कि जांच में कथित हेराफेरी की वास्तविक राशि कितनी सामने आती है और प्रभावित खाताधारकों की शिकायतों का समाधान किस तरह किया जाता है।

डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन की कार्यकारिणी का हुआ गठन

ड्रग वेयर हाऊस महराजगंज में बैठक करते डी फार्मे एसोसिएशन के अध्यक्ष व सदस्यगण

– रामकृष्ण बने जिला मीडिया प्रभारी
दैनिक स्वाभिमान जागरण
महराजगंज



ड्रग वेयर हाऊस महराजगंज में बुधवार को डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन की बैठक की गई। जिसमें रामकृष्ण जायसवाल को संघ का जिला मीडिया प्रभारी, आशुतोष त्रिपाठी को कार्यकारिणी अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाया गया। साथ ही दीनानाथ पटवा को संघ का प्रवक्ता बनाया गया है। इसके बाद संघ ने कार्यकारिणी सदस्यों का भी चयन किया। जिसमें तेज बहादुर पटेल, सत्य प्रकाश चौबे, चंद्रभूषण शुक्ला, आशुतोष कुमार, इम्तियाज अहमद व राजेश अग्रहरि को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। इसके बाद संघ के जिला अध्यक्ष ने संघ की मजबूती व जिला के फार्मासिस्टों की समस्याओं को हल करने हेतु सभी को एकजुट रहने का आह्वान किया। इसके बाद प्रांतीय संघ के आह्वान पर 13 नवंबर को लखनऊ में होने वाले प्रदर्शन पर चर्चा किया गया। इस अवसर पर संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह, मंत्री सतीशचंद्र पटेल,बैजनाथ शर्मा, बैजनाथ यादव,तेज बहादुर पटेल, संजय उपाध्याय व रमेश यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

आगरा पुलिस ने तो हद ही कर दीः अधिवक्ता को धरने पर बैठना पड़ा, तब लिखी लूट की एफआईआर

संवाददाता
आगरा। आगरा के थाना सिकंदरा के आवास विकास कॉलोनी सेक्टर दस में अधिवक्ता से 2 लाख रुपये सहित कार ले जाने के मामले में लूट की प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में कार मालिक, उसके भाई और अन्य को आरोपी बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि लेन–देन के विवाद की बात सामने आई है। साक्ष्य संकलन कर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कार्रवाई के लिए अधिवक्ता ने दीवानी में धरना प्रदर्शन किया था। तब पुलिस ने कार्रवाई की है। सिकंदरा निवासी अधिवक्ता संदीप शर्मा ने बताया कि उनके भाई नितिन शर्मा अपने मित्र जितेंद्र की कार को 29 सितंबर को एसी ठीक कराने के लिए लिया था। एक अक्तूबर की रात नौ बजे आवास विकास सेक्टर 10 कार लेकर आए थे। बालूगंज निवासी चाचा से दो लाख रुपये लेकर आए। यह रकम कार में ही रखी हुई थी। रास्ते में दो युवकों ने गाड़ी को रोक लिया। विरोध पर मारपीट करने लगे। एक युवक ने कमर में हाथ लगाया। उन्हें लगा



कि उसके पास कोई हथियार है। डर की वजह से कार से बाहर निकल आए। आरोपी कार लूटकर भाग गए। आरोप लगाया कि यह घटना अनुज सिसौदिया और उसके भाई शिवम सिसौदिया ने अंजाम दी है। मामले में सिकंदरा पुलिस से शिकायत की मगर सुनवाई नहीं हुई। तीन दिन पहले अधिवक्ता ने दीवानी परिसर में धरना शुरू कर दिया। सोमवार को एसीपी सदर अमीषा और एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने दीवानी पहुंचकर जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब धरना समाप्त हो सका। मंगलवार को थाना सिकंदरा में अधिवक्ता के भाई नितिन शर्मा की तहरीर पर अनुज सिसौदिया, उसके भाई शिवम सिसौदिया और अन्य पर लूट समेत अन्य धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि मामले में कार ले जाने का आरोप लगाया है। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। लूटी गई कार आरोपियों ने पूर्व में लिखित अनुबंध कर मित्र जितेंद्र के पास एक लाख रुपये उधार लेकर गिरवी रखी थी। आरोपियों की मां ने पूर्व में कोतवाली थाने में शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि कार को जबरन अपने पास रख लिया है। जांच में मामला लेनदेन के विवाद का निकलने पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी।

आगरा में सपा ने फिर भाजपा को दी पटखनी, शिक्षक एमएलसी सीट पर आकाश अग्रवाल जीते

संवाददाता
आगरा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक सीटों के चुनाव में आगरा से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों के लिए जीत की खबर आई है। आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर भाजपा को झटका दिया है। वहीं, आगरा खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गुरुजी ने सपा के शशांक यादव को हराकर अपनी सीट बरकरार रखी। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में विजयी घोषित होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर नरेंद्र प्रताप ने बुधवार को डॉ. आकाश अग्रवाल को जीत का प्रमाणपत्र सौंपा। हालांकि, प्रशासन की ओर से मतों के अंतिम आधिकारिक आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं कराए गए। प्रमाणपत्र मिलने के बाद आकाश अग्रवाल को मीडिया से बातचीत का अवसर भी नहीं मिला। उन्हें पुलिस सुरक्षा के बीच मतगणना स्थल के पिछले गेट से बाहर ले जाया गया। इस दौरान उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुटी रही। उधर, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जीत के बाद भाजपा प्रत्याशी डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने पार्टी की



सफलता का श्रेय कार्यकर्ताओं की मेहनत और सरकार के कामकाज को दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों, स्नातकों, अधिवक्ताओं और पत्रकारों का समर्थन भाजपा को मिला है, जिसके परिणामस्वरूप पार्टी ने जीत दर्ज की है। मानवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा ने जो वादे किए, उन्हें पूरा करने का प्रयास किया है। उन्होंने रोजगार, सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता, प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना और एक जिला, एक उत्पाद जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में बिना खर्ची और बिना पर्ची के सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले सैफई और रामपुर का सिंडिकेट नौकरियों पर डाका डालता था जबकि अब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जा रही है और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। आगरा के पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत मतगणना की प्रक्रिया पूरी कराई गई। एक निर्वाचन क्षेत्र में विजेता की घोषणा कर दी गई है, जबकि दूसरे में अंतिम मतगणना की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी। उन्होंने कहा कि पूरी गणना शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि दोनों विजयी प्रत्याशियों को सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू होने के कारण किसी भी तरह का विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्याशियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। मतगणना के दौरान रात में हुए हंगामे से जुड़े सवाल पर दीपक कुमार ने कहा कि संबंधित प्रक्रिया मतगणना स्थल के अंदर हुई थी और बाहर किसी तरह की घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पुलिस को अब तक किसी की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस कमिश्नर ने मतगणना में तैनात पुलिसकर्मियों, मतदानकर्मियों और पत्रकारों का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि मतपत्रों से होने वाली मतगणना की प्रक्रिया लंबी होती है और पुलिसकर्मी सुबह पांच बजे से लगातार ड्यूटी पर तैनात रहे।

ट्रक ने 2 महिलाओं को कुचला, मौत,सड़क पार करते समय हादसा

संवाददाता
ग्रेटर नोएडा। कासना थाना क्षेत्र में मंगलवार रात तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से सड़क पार कर रहीं दो महिलाओं की मौत हो गई। हादसा कासना यूपीसीडा कंपनी कट के सामने चौराहे पर हुआ। टक्कर मारने



के बाद चालक ट्रक लेकर सिरसा की तरफ भाग निकला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायल महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आगे जाकर ट्रक को रोककर कब्जे में लिया और चालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार, हादसे में बदायूं जिले के जरीफनगर थाना क्षेत्र के दहगवां गांव निवासी मनीषा (45) और हिम्मतपुर गांव निवासी विमलेश (43) गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। दोनों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। दोनों महिलाएं एक निजी कंपनी में कार्य करती थीं। हादसे की सूचना मिलते ही कासना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक की तलाश शुरू की। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है। दोनों महिलाओं के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मृतक महिलाओं के स्वजन की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

आगरा एमएलसी चुनावः सपा प्रत्याशी 3,698 वोटों से आगे, भाजपा प्रत्याशी ने छोड़ी मतगणना; सुबह 5 बजे चले गए

संवाददाता
आगरा। विधान परिषद के आगरा खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना की प्रक्रिया मंगलवार सुबह आठ बजे भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई। बंडल तैयार होने के बाद दोपहर करीब 12 बजे शिक्षक सीट और शाम सात बजे स्नातक सीट के मतों की गिनती 14–14 टेबल पर शुरू हुई। सुबह चार बजे तक 29865 मतपत्रों की मतगणना हो चुकी है, जिसमें सपा के डॉ. आकाश अग्रवाल वित्त विहीन वाले को कुल 13,087 मत मिले हैं। वहीं भाजपा के हरी किशोर तिवारी को 9,389 मत प्राप्त हुए हैं। अब वरीयता के अनुसार मतगणना के राउंड शुरू हुए हैं जिसमें सर्वप्रथम दूसरी वरीयता की मतगणना की जा रही है। वहीं भाजपा प्रत्याशी हरिकिशोर तिवारी का मतगणना स्थल पर चल रहा धरना खत्म हो गया। मांगें पूरी नहीं होने से नाराज तिवारी अपने साथियों के साथ मतगणना प्रक्रिया बीच में छोड़कर चले गए, जबकि मतगणना जारी है। शिक्षक सीट के मतों की गिनती शुरू होने के साथ ही समाजवादी पार्टी के शिक्षक प्रत्याशी



डॉ. आकाश अग्रवाल ने बढ़त बना ली। हर टेबल पर आकाश को भाजपा के हरिकिशोर तिवारी से ज्यादा वोट मिले। हालांकि, आकाश लगातार मतगणना की व्यवस्था और निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए विरोध जताते रहे। वहीं, स्नातक निर्वाचन सीट के लिए मतों के बंडल बनाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शाम को गिनती शुरू हुई। पूरे दिन सियासी पारा गर्म रहा। फिरोजाबाद रोड स्थित गल्ला मंडी में बने मतगणना स्थल पर सुबह से ही प्रशासनिक सख्ती और गहमागहमी का माहौल रहा। सबसे पहले मतपेटियों को खोलकर वोटों की छंटनी की गई और मतों के बंडल बनाने की प्रक्रिया सुबह आठ बजे शुरू हुई। मतगणना स्थल पर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर टेबल पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। सपा के स्नातक प्रत्याशी शशांक यादव उर्फ सीटू ने मतगणना में गड़बड़ी के आरोप लगाए। चुनावी मैदान में शिक्षक सीट से 12 और स्नातक सीट से 13 प्रत्याशी हैं। 23 अक्तूबर को हुए मतदान में आगरा समेत 12 जिलों के शिक्षक के करीब 30 हजार और स्नातक के 90 हजार मतदाताओं ने मतदान किया था। गड़बड़ी के आरोपों के बाद शिक्षक सीट के लिए तीन बूथों पर 26 अक्तूबर को पुनर्मतदान हुआ था। सपा प्रत्याशी और नेताओं ने प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए, जिसे चुनाव अधिकारियों ने सिरे से खारिज कर दिया। शाम करीब छह बजे मतगणना स्थल के बाहर हंगामा कर रहे सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती बरतते हुए सभी को वहां से खदेड़ा।

पति से विवाद में महिला ने खेत में फांसी लगाकर दी जान

संवाददाता
उरई/जालौन। जालौन के चुर्खी थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में मंगलवार शाम 60 वर्षीय महिला ने खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, बाजार से लौटते समय पति के शराब पीने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद महिला खेत पर चली गई, जहां उसका शव नीम के पेड़ पर फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की पहचान जलालपुर गांव निवासी पानकुंवर के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक, वह खेती–किसानी करके परिवार का भरण–पोषण करती थीं। हाल में बारिश के कारण खरीफ की फसल खराब हो गई थी, जिससे वह आर्थिक परेशानी और फसल के नुकसान को लेकर चिंतित थीं। जानकारी के अनुसार, मंगलवार को पानकुंवर अपने पति के साथ बाजार गई थीं। थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार के मुताबिक, बाजार से लौटते समय पति के शराब पीने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद महिला खेत पर चली गई। जब वह काफी देर तक घर नहीं लौटीं तो परिजन उनकी तलाश में खेत पहुंचे। वहां नीम के



पेड़ पर उनका शव फंदे से लटका मिला। महिला की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर चुर्खी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। परिजनों ने फसल खराब होने से महिला के परेशान रहने की बात कही है। वहीं, पुलिस ने पति–पत्नी के बीच विवाद की जानकारी दी है। थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

रायन इंटरनेशनल स्कूल ने टाइम्स एजुकेशन आइकन्स 2026 में हासिल की पहली रैंक

संवाददाता
ग्रेटर नोएडा। रायन इंटरनेशनल स्कूल, ग्रेटर नोएडा ने टाइम्स एजुकेशन आइकन्स 2026 (नॉर्थ) में प्रतिष्ठित सम्मान हासिल किया है। स्कूल को ग्रेटर नोएडा जोन की चौलेंजर्स श्रेणी में पहली रैंक मिली है। स्कूल की प्रधानाचार्या सुश्री सुधा सिंह ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। स्कूल प्रबंधन के अनुसार, यह उपलब्धि शैक्षणिक उत्कृष्टता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस रैंकिंग में शैक्षणिक प्रदर्शन, बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम, शिक्षकों की गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे, पाठ्येतर गतिविधियों और विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान देने जैसे विभिन्न मानकों के आधार पर स्कूलों का मूल्यांकन किया जाता है। इस उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधन ने सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को बधाई दी।

6 साल 6 महीने की जेलः बिक गई 15 बीघा जमीन...घर भी रखना पड़ा गिरवी, बेगुनाही की लड़ाई में तब मिली जीत

संवाददाता
आगरा। अपहरण और हत्या के आरोप में 6 वर्ष 6 महीने और 23 दिन सलाखों के पीछे काटने वाले रुनकता



निवासी अरुण कुमार उर्फ दीपक को सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। परिजन का कहना है कि न्याय पाने के लिए पूरे परिवार को आर्थिक संकट से जूझना पड़ा। बेटे को बेगुनाह साबित करने की कानूनी जंग में पिता की 15 बीघा जमीन बिक गई। मकान भी 15 लाख रुपये में गिरवी हो गया। 6 लाख रुपये के मुआवजे को पिता ने काफी कम बताया। रुनकता निवासी राकेश कुमार ने बताया कि 13 नवंबर 2019 को पुलिस अरुण को घर से ले गई थी और अगले दिन जेल भेज दिया। जेल जाने से पहले बेटा अरुण बीटीसी की पढ़ाई कर रहा था। वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तब उसका बेटा 2 वर्ष का था, जोकि अब 9 वर्ष का है। अरुण बेटे के बचपन के उन कीमती वर्षों में उसके साथ नहीं रह सका। यह सब पुलिस की लापरवाही से हुआ। बेटे को बेगुनाह साबित करने के लिए परिवार को सत्र न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी करनी पड़ी। इस वजह से जलेसर के गांव भींतर में स्थित 15 बीघा जमीन बिक गई। रुनकता का मकान भी 15 लाख रुपये में गिरवी रखना पड़ा। 6 लाख रुपये की मुआवजा राशि मिलने के बाद भी दर्द की भरपाई नहीं हो सकती। मां रामवती का कहना है कि बेटे का पूरा जीवन बर्बाद हो गया। वह अपने बच्चे को पिता का प्यार नहीं दे पाया। हर दिन यही आस रहती थी कि कब उसे निर्दोष साबित करा पाएंगे। एक भी रात ठीक से नहीं सोई। आखिर में न्याय मिला।

दिवाली से पहले आफत, बढ़ रही स्किन एलर्जी की समस्या, एसएन की ओपीडी में उमड़ रही मरीजों की भीड़

संवाददाता
आगरा। आगरा में दिवाली की जगमगाती तैयारियों के बीच घरों में रंग–रोगन और साफ–सफाई का दौर जोरों पर है। अब यह भागदौड़ सेहत पर भारी पड़ रही है। धूल–मिट्टी और केमिकल्स के संपर्क में आने से एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में त्वचा रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एसएन मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. यतेंद्र चाहर ने बताया कि इन दिनों मरीजों में त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ने, अर्टिकेरिया (पित्ती) और एटोपिक डर्मेटाइटिस की शिकायतें काफी बढ़ गई हैं। इस सीजन में अस्पतालों में भी मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंगलवार को एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में कुल 3,639 मरीज पहुंचे, जिनमें 988 नए और 2,651 पुराने मरीज शामिल रहे। अकेले त्वचा रोग विभाग में ही लगभग 320 मरीज जांच और इलाज के लिए पहुंचे।



विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि साफ–सफाई और पेंट आदि करते और करवाते समय चेहरे पर मास्क, हाथों में दस्ताने और आंखों में चश्मे का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि धूल और केमिकल्स के हानिकारक प्रभावों से बचा जा सके। घर की सफाई और पेंट–पुट्टी का काम करते समय हाथों में दस्ताने जरूर पहनें। साफ–सफाई का काम करते समय चश्मा लगाना न भूलें। त्वचा में नमी बरकरार रखने के लिए नियमित मॉइश्चराइजर लगाएं। जिन्हें पहले से एलर्जी की समस्या है, वो धूल और केमिकल से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें।

स्वाभिमान जागरण
हिन्दी दैनिक
स्वामी, प्रकाशक मुद्रक एंव सम्पादक इम्तियाज़ अंसारी द्वारा सुपीरियर प्रिन्टर्स 245 माहम सिटी तिकोनिया पारा लखनऊ,(उ०प्र०)–11 से मुद्रित एवं मीडिया हाउस 20ए शिवाजीमार्ग हुसैनगंज लखनऊ उ0प्र0–01 से प्रकाशित।
संपादक
आलोक कुमार केसरवानी
प्रधान संपादक
इम्तियाज़ अंसारी
6392273876
Email-dainikswabhimanjagran.india@gmail.com
उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं अस्थाई है समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ मान्य होगा।